पूरी बेंच

समक्ष एस.एस. संधावालिया, सी.जे., पी.सी. जैन और एस.सी. मितल, जे.जे.

लछमन सिंह, अपीलकर्ता।

बनाम

गुलज़ारी और अन्य,-प्रतिवादी।

1974 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 776।

25 नवंबर 1983.

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम (1961 का XVIII) - धारा 2 (जी) और (एच), 3 और 4 - आबादी देह के भीतर एक गैर-मालिक के स्वामित्व वाले घर के तहत भूमि - ऐसी भूमि शामिलात देह का हिस्सा नहीं है - भूमि में स्वामित्व - क्या शमिलत कानून के प्रारंभ पर गैर-मालिक में निहित माना जाएगा।

माना गया कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 4(एल)(बी) के प्रावधान आबादी देह के भीतर स्थित भूमि पर लागू होते हैं (इस तथ्य के बावजूद कि वे शामिलात देह की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं) उक्त अधिनियम की धारा 2(जी) या नहीं), जो उक्त अधिनियम की धारा 2(एच) में परिभाषित शमिलत कानून के प्रारंभ होने पर या उससे पहले एक गैर-मालिक के स्वामित्व वाले घर के अंतर्गत है। इसमें मुख्य विचार भूमि पर एक घर का निर्माण और एक गैर-मालिक द्वारा इसके स्वामित्व का तथ्य है। विधायी मंशा स्पष्ट रूप से उन गैर-मालिकों को वैधानिक आश्रय देना है, जिन्होंने अपने श्रम से अपने सिर पर आश्रय बनाया था, भले ही वह भूमि जिस पर वह खड़ी थी, स्वामित्व निकाय की थी या किसी व्यक्तिगत मालिक में निहित थी। हालाँकि, यह आवश्यक रूप से शमिलत कानून के प्रारंभ होने से पहले होना था जैसा कि अब अधिनियम में धारा 2 (एच) द्वारा परिभाषित किया गया है।

(पैरा 13 और 17).

अजायब सिंह और काका सिंह बनाम उपमंडल अधिकारी और अन्य,

1976 पी.एल.जे. 489.

रघबीर सिंह बनाम राजा राम और अन्य, 1965 करंट लॉ जर्नल 154।

खारिज कर दिया गया।

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता द्वारा 10 दिसंबर, 1982 को मामले को एक खंडपीठ को भेजा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.वी. गुप्ता की खंडपीठ ने 27 मई को मामले को फिर से पूर्ण पीठ को भेज दिया। 1983. पूर्ण पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया शामिल थे। माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. सी. मित्तल ने अंततः 25 नवंबर, 1983 को मामले का फैसला किया)। श्री जे.सी. नागपाल की अदालत के आदेश से नियमित द्वितीय अपील। वरिष्ठ उप-न्यायाधीश. सोनीपत ने दिनांक 29 दिसंबर, 1973 की बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ श्री एच.सी. गुप्ता, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, गोहाना की दिनांक 21 अक्टूबर, 1972 की पुष्टि करते हुए वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया।

अपीलकर्ता की ओर से एस. सी. कपूर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से भाल सिंह मलिक, अधिवक्ता।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

1. क्या पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 4(1)(बी) के प्रावधान आबादी देह के भीतर स्थित भूमि पर लागू होते हैं (इस तथ्य के बावजूद कि यह शामिलात देह की परिभाषा के अंतर्गत आता है) उक्त अधिनियम की धारा 2(जी) या नहीं), जो शामिलात कानून के प्रारंभ होने पर या उससे पहले एक गैर-मालिक के स्वामित्व वाले घर के अधीन है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 2(एच) में परिभाषित है--है पूर्ण पीठ के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण प्रश्न की आवश्यकता है।

2. उपरोक्त मुद्दे से संबंधित तथ्यों को सापेक्ष संक्षिप्तता के साथ देखा जा सकता है। लछमन सिंह वादी-अपीलकर्ता ने 30 अप्रैल 1935 को मालिक के रूप में कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था, उनके पिता ने प्रतिवादी नंबर 1 से 4 के पूर्व हितैषी ज्ञानी तेली को यह जगह पट्टे पर दी थी। रुपये की दर. 2/- प्रति वर्ष और उक्त ज्ञानी तेली ने उस पर एक घर का निर्माण किया था। 12 अक्टूबर को. 1965 में, उक्त ज्ञानी तेली ने विवादग्रस्त स्थल का एक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में बेच दिया और अपना कब्जा उसे सौंप दिया और इसके बाद वे दोनों विवादग्रस्त पूरे स्थल के मालिक होने का दावा करने लगे। दावा उस भूमि पर निर्माण (मलबा) हटाकर कब्जे की डिक्री के लिए था।

3. मुकदमा लड़ने में प्रतिवादियों की दलील यह थी कि ज्ञानी तेली, जो प्रतिवादी नंबर 1 के पिता थे, मुकदमे की जमीन के मालिक थे और उन्होंने प्रतिवादी नंबर 5 को उसका एक हिस्सा वैध रूप से बेच दिया था। किसी भी किराया नोट या लीज डीड से इनकार कर दिया गया था। आगे यह दलील दी गई कि डी नंबर 5 ने रुपये की राशि खर्च की थी। उसे बेची गई वाद भूमि के एक हिस्से पर भवन निर्माण पर 15,000/- रु. यह दावा किया गया था कि गांव बुटाना के आबादी देह में जमीन का मालिकों के बीच कोई बंटवारा नहीं हुआ था, और ज्ञानी तेली (और उनसे पहले भी उनके पूर्वज) एक गैर-मालिक के रूप में विवादित स्थल पर काफी समय से कब्जा कर रहे थे। लंबे समय तक। इस प्रकार वह पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 4(1) (बी) के प्रावधानों के मद्देनजर अपने आवासीय घर के तहत विवादित स्थल का मालिक बन गया था ।

4. पक्षों की दलीलों पर ट्रायल कोर्ट ने आठ मुद्दे तय किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा निम्नलिखित शर्तों में मुद्दा संख्या 6 है:--

"क्या ज्ञानी तेली विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट के तहत घर का मालिक बन गया था?"

ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया और मुद्दा संख्या 6 पर उसका निष्कर्ष यह था कि ज्ञानी तेली पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट के प्रावधानों के तहत विवाद में साइट का मालिक बन गया था । अपील में ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष को कायम रखा गया। अपीलकर्ता इस नियमित द्वितीय अपील के माध्यम से आया है।

5. यह अपील मूल रूप से एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आई थी। उनके समक्ष, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई थी कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (इसके बाद 1961 एक्ट कहा जाएगा) की धारा 3(1) धारा 4 के कुछ हद तक व्यापक रूप से प्रचलित प्रावधानों को नियंत्रित और सीमित करती है। (1)(बी) और परिणामस्वरूप बाद वाला खंड या तो आबादी देह के भीतर की भूमि पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है या किसी भी मामले में केवल तभी लागू होता है जब वह धारा 2 (जी) के तहत शामिलात देह की परिभाषा के अंतर्गत आता है । प्रश्न का कोई महत्व नहीं होने और इस मुद्दे पर इस न्यायालय के भीतर प्राधिकार के स्पष्ट टकराव के कारण, मामले को एक आधिकारिक निर्णय के लिए एक डिवीजन बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। कुछ इसी तरह के कारणों से, डिवीजन बेंच ने मामले को एक और भी बड़ी बेंच के पास निर्णय के लिए भेज दिया है।

6. हमारे सामने, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एस.सी. कपूर ने धारा 3(1) पर शाब्दिक रूप से यह तर्क दिया कि अधिनियम केवल उन भूमियों पर लागू हो सकता है जो धारा 2 के खंड (जी) में परिभाषित अनुसार शामिल थीं। अधिनियम का. इस आधार पर, यह तर्क दिया गया कि सबसे पहले सीमा परीक्षण यह है कि क्या भूमि शमिलत देह की परिभाषा के अंतर्गत आती है जैसा कि धारा 2 (जी) में वर्णित है ? यदि ऐसा होता है, तभी उस पर वर्तमान अधिनियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। नतीजतन, यह तर्क दिया गया कि यहां भूमि आबादी देह के भीतर थी और अपीलकर्ता या उसके पूर्ववर्तियों के व्यक्तिगत स्वामित्व में थी और इस प्रकार धारा 2 (जी) के तहत परिभाषा से बाहर थी, धारा 4 (1) के प्रावधान) स्थिति के प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे। संक्षेप में, तर्क यह था कि धारा. 4(1)(बी) धारा 3 की उप-धारा (1) के प्राथमिक प्रावधान के अधीन और शासित था। अपने रुख के समर्थन में, वकील ने रघबीर सिंह बनाम राजा राम, 1965 क्यूआर एलजे 154 पर बहुत अधिक भरोसा किया; तारा चंद बनाम पंजाब राज्य 1971 पंजाब एलजे 808; और अजायब सिंह बनाम उपमंडल अधिकारी, सिविल, खरड़, 1976 पुं एलजे 489।

7. उपरोक्त तर्क का उसके सभी पहलुओं में मूल्यांकन करने के लिए प्रावधानों के विधायी इतिहास का सहारा लेना अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का उपयोग विधेयक पेश किए जाने के समय प्रचलित प्रावधानों और उस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है जिसके लिए इसे प्रायोजित किया गया था: हालाँकि, वैधानिकता से परे जाना अनावश्यक लगता है इस क्षेत्र के भीतर शमिलत कानून का संहिताकरण, सबसे पहले पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1953 (1954 का एक्ट नंबर 1) (इसके बाद 1953 का एक्ट कहा जाएगा) के साथ शुरू हुआ और इसके बाद पेप्सू विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) लागू हुआ।) अधिनियम, 1954 (इसके बाद इसे 1954 पेप्सू अधिनियम कहा जाएगा)। पहले भी, यह अच्छी तरह से मान्यता थी कि ग्रामीण बढ़ई, लोहार, चर्मकार, नाई, धोबी आदि जैसे कृषि कारीगरों के एक समूह का बसना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग था। फिर भी, उपरोक्त क़ानूनों के अधिनियमित होने से पहले, गाँव की संपत्ति में शमिलत और आम भूमि के संबंध में विवादास्पद मुकदमेबाजी चल रही थी। इसमें अक्सर गांव के मालिकाना निकाय या व्यक्तिगत भूमिधारकों को, कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण तरीके से, गैर-मालिकों के खिलाफ खड़ा किया जाता था। व्यक्तिगत गुणों के अलावा, ऐसे मामले प्रत्येक गाँव की संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों के साथ-साथ गैर-मालिकों के विरुद्ध मालिकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट प्रचलित रीति-रिवाजों पर भी आधारित थे। इस गंभीर असंतोषजनक स्थिति का समाधान करने के लिए और, विशेष रूप से, गाँव की आबादी में गैर-मालिकों को उनके सिर पर कुछ हद तक आश्रय प्रदान करने के लिए विधानमंडल को पहले कुछ हद तक संक्षिप्त अधिनियम बनाकर कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था (10 में से) अनुभाग) पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 (1954 का अधिनियम संख्या 1)। अधिनियम के उद्देश्य और कारण शिक्षाप्रद हैं और विस्तार से ध्यान देने योग्य हैं:--

"जब गांवों की मूल स्थापना हुई थी तो यह माना जाता था कि शामिलात वास्तव में गांव के सभी निवासियों के उपयोग के लिए थी। वर्तमान में स्थिति यह है कि सभी शामिलात गांव के मालिकाना निकाय की संपत्ति हैं और उनके अधिकार हैं गैर-मालिक वर्ग कुछ उद्देश्यों के लिए अनुदान के रूप में हैं, हालांकि गैर-मालिक वर्ग भी संभवतः अपने संस्थापकों के साथ गांवों में बस गए हैं और कृषि संचालन से संबंधित मामलों में मालिकाना निकाय को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान लाभ नहीं मिलता है। शामिलात भूमि पर उनका अधिकार है और वे आबादी में भी अपने घरों के नीचे की जगहों के मालिक नहीं हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ-साथ हरिजनों और इसी प्रकार के अन्य गैर-मालिकाना वर्गों के लिए अहितकारी स्थितियाँ प्रचलन में आ गई हैं, जहाँ तक शमिलत भूमि में आवश्यक अधिकारों के उपभोग का संबंध है, वे अपनी स्थिति को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें अपने आवासीय मकानों के स्थलों पर मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। इस बात पर इन वर्गों के सदस्यों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है। सरकार का मानना है कि ये स्थितियां अब नहीं रहनी चाहिए। गांवों में इन वर्गों के निवासियों को सुरक्षा और आत्म-सम्मान के साथ जीने का अवसर देने के उद्देश्य से ही प्रस्तावित कानून बनाया जा रहा है। (पंजाब गजट, असाधारण, दिनांक 6 अप्रैल, 1953 में प्रकाशित उद्देश्यों और कारणों का विवरण देखें)।"

इतिहास के मामले में, यह ध्यान देने योग्य है कि बाद में पेप्सू विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1954, 11 मार्च 1955 से लागू किया गया था। उक्त क़ानून पंजाब की सहयोगी क़ानून और यहाँ तक कि समरूपता में था। वस्तुओं और उनके कारणों का विवरण पूर्व की कार्बन प्रति मात्र था। 1 नवंबर 1956 को, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर , पंजाब और पेप्सू राज्यों का विलय कर दिया गया, लेकिन दोनों बहन क़ानून क्रमशः पंजाब और पेप्सू के क्षेत्रों में लागू रहे। इस दौरान। पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1956 तत्कालीन पंजाब के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी नहीं दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शमिलत कानूनों के प्रशासन के दौरान समय-समय पर कुछ दोष और चूक का अनुभव किया गया था और आगे विधानमंडल ने पंजाब के पूरे नए राज्य के लिए एक समान कानून अपनाने की इच्छा जताई, जिसमें पहले के पंजाब और पेप्सू क़ानून के प्रावधानों को शामिल किया गया था, इन कारणों से, वर्तमान पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 को क़ानून की किताब में लाया गया और, अन्य बातों के साथ, वस्तुओं और कारणों का विवरण निम्नानुसार बताया गया है:

"पूर्वव्यापी प्रभाव से 'शामिलत देह' की एक व्यापक परिभाषा प्रदान की गई है। विधेयक में शामिलात का उपयोग करने का भी प्रावधान है। बेदखल किए गए या बेदखल किए गए किरायेदारों के निपटान के लिए गांव के कुल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र और वहां छोटी-छोटी जोतों का आकार बढ़ाने के लिए; शामिल भूमि के किराए के बकाया को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने योग्य बनाने के लिए और शामलार भूमि पर अतिक्रमण हटाने को अधिकृत करने के लिए"

8. उपरोक्त से यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि 1954 में शामिलात कानून लागू होने से पहले, मौजूदा कानून बेहद असंतोषजनक स्थिति में पाया गया था। शामिलात देह की कोई परिभाषा मौजूद नहीं थी और न ही उस पर लागू कोई समान कानून मौजूद था। समय के दौरान, मालिकाना निकाय या व्यक्तिगत भूमिधारकों की तुलना में गैर-मालिकों के अधिकार पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, जिससे उन्हें नुकसान हुआ था। अन्य बातों के साथ-साथ, स्थिति यह थी कि गैर-मालिकाना वर्ग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बावजूद, वे मालिक भी नहीं थे। आबादी क्षेत्र के भीतर उनके घरों के नीचे की जगहें और इस प्रकार वे अपने ऊपर आश्रय के संबंध में भी पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करते थे। सिर. इस विशिष्ट बिंदु पर, क़ानून द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपायों के लिए तर्क यह था कि आश्रय और सुरक्षा की छतरी उन गैर-मालिकों के लिए मौजूद होनी चाहिए, जिन्होंने अनादि काल से, मालिकाना निकाय को सेवाएं प्रदान की थीं, जिसके लिए उन्हें विस्तारित किया गया था। आबादी देह के भीतर सामान्य भूमि पर घर बनाने की रियायत या अधिकार। विधानमंडल द्वारा प्रदान किया गया विशेष उपाय इस लंबे समय से चले आ रहे कब्जे को मान्यता देना और ऐसी भूमि को गैर-मालिकों के घरों के अधीन करना था

9. अब 1961 अधिनियम के उन विशेष प्रावधानों के विज्ञापन के लिए मंच तैयार है जो निर्माण के लिए आते हैं, जिससे निर्माण के लिए शमिलत कानून बनता है। इस प्रकार, अधिनियम के प्रयोजन के लिए शमिलत कानून को सटीक रूप से निम्नानुसार परिभाषित किया गया था: -

"2 (ज)--'शमिलात कानून' का अर्थ है-

(i) उस क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में, जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पहले, पंजाब राज्य में शामिल थी, पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953; या

(ii) उस क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में, जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पहले, पटियाला राज्य और पूर्वी पंजाब राज्य संघ में शामिल था। पेप्सू विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम, 1954। "

10. फिर, 1961 अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के महत्व की सही मायने में सराहना करने के लिए , इसे 1953 अधिनियम (पंजाब अधिनियम संख्या 1) की धारा 3(बी) के साथ तुलना करना शिक्षाप्रद और वास्तव में आवश्यक है। 1954 का):--

1953 अधिनियम 3. पंचायतों और गैर-मालिकों में अधिकारों का निहित होना--तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, और किसी समझौते, साधन, प्रथा या प्रथा या किसी डिक्री या आदेश के बावजूद। कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी, भूमि के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित - (ए) * * * * * * * * * (बी) जो किसी गांव के आबादी देह में स्थित है और जो स्वामित्व वाले घर के अधीन है एक गैर-मालिक द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ में उक्त गैर-मालिक में निहित होगा। 1961 अधिनियम 4. पंचायतों और गैर-मालिकों में अधिकारों का निहित होना। (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून या किसी समझौते, लिखत, प्रथा या प्रथा या किसी डिक्री, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के आदेश में किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी; भूमि के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित - (ए) * * * * * * * * * (बी) जो किसी गांव के आबादी देह के भीतर या बाहर स्थित है और जो गैर-मालिक के स्वामित्व वाले घर के अंतर्गत है , शमिलत कानून के प्रारंभ पर, ऐसे गैर-मालिक में गहरा निहित माना जाएगा।

11. सबसे पहले, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1953 के अधिनियम में भी शामिलात देह की कोई परिभाषा नहीं थी। 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के आधार पर ही इसकी एक सटीक और व्यापक परिभाषा अधिनियमित की गई थी। समान रूप से, 1953 अधिनियम में, 1961 अधिनियम की वर्तमान धारा 3 के समकक्ष कोई प्रावधान नहीं था। यह स्पष्ट है कि 1961 के अधिनियम में कुछ प्रावधानों को इस तथ्य के मद्देनजर पेश किया जाना था कि यह पहले के शमिलत कानून को प्रतिस्थापित करना था जिसे इसके लागू होने पर निरस्त किया जाना था।

12. अब उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या करने से पहले इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक है कि गैर-मालिकों के स्वामित्व वाले घरों के तहत भूमि का निहितार्थ, 1953 के पंजाब अधिनियम के तहत 9 जनवरी, 1954 की कट-ऑफ तारीख से सीधे संबंधित है। धारा 4 के दोनों खंड (ए) और (बी) ने धारा 2 (एच) में परिभाषित शमिलत कानून की शुरुआत के लिए बाहरी सीमा तय की । जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, क़ानून का औचित्य उस विशेष तिथि पर गैर-मालिकों के लंबे समय से चले आ रहे तथ्य को मान्यता देना था, जिन्हें पहले मालिकाना निकाय को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में आवास के लिए जगह दी गई थी, जो विधायिका चाहती थी। ऐसे मकानों की रक्षा करना और उनके अधीन भूमि को उनमें निहित करना। हालाँकि, ऐसा नहीं है कि इस कट-ऑफ तिथि के बाद भी भूमि के मालिकों को किसी भी या हर गैर-मालिक और अतिचारी द्वारा स्वामित्व से वंचित किया जाता रहेगा, जो दूसरे की भूमि पर अनधिकृत रूप से घर बनाने का विकल्प चुन सकता है। 1961 अधिनियम की धारा 4(1)(ए) और (बी) को

परिणामस्वरूप कट-ऑफ तिथि के इस बुनियादी पैरामीटर के भीतर समझा जाना चाहिए जो शामिलात कानून की शुरुआत है।

13. अब धारा 2(एच) के तहत शामिलात कानून की परिभाषा और 9 जनवरी, 1954 की श्रेणियों की कट-ऑफ तारीख के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में देखा गया। धारा 4(1)(बी) की भाषा स्वयं स्पष्ट है। इसमें मुख्य विचार भूमि पर एक घर का निर्माण और एक गैर-मालिक द्वारा इसके स्वामित्व का तथ्य है। विधायी मंशा स्पष्ट रूप से उन गैर-मालिकों को वैधानिक आश्रय देना है, जिन्होंने अपने श्रम से अपने सिर पर आश्रय बनाया था, भले ही वह भूमि जिस पर वह खड़ी थी, मालिकाना निकाय की थी या किसी व्यक्तिगत मालिक में निहित थी। हालाँकि, यह आवश्यक रूप से शमिलात कानून के प्रारंभ होने से पहले होना था जैसा कि अब अधिनियम की धारा 2(एच) द्वारा परिभाषित किया गया है ।

14. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उन पर विचार करना बाकी है। तारा चंद के मामले (1971 पुन एलजे 808) (सुप्रा) में , जो कि 1961 की एक नियमित दूसरी अपील थी, मामले को नए निर्धारण के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया था क्योंकि कानून के अधिनियमन द्वारा लाए गए बदलाव के कारण उच्च न्यायालय में दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान 1961 अधिनियम। मामला मुख्य रूप से इस आधार पर आया और पैराग्राफ 4 में पारित अवलोकन न तो अनुपात है और न ही इस प्रस्ताव का कोई वारंट है कि 1961 अधिनियम की धारा 4(1)(बी) आबादी देह के भीतर की भूमि पर लागू नहीं है। दरअसल, डिवीजन बेंच द्वारा इस विशिष्ट खंड का दूर-दूर तक कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। इस प्रकार उक्त मामला अलग है।

15. फिर, अजायब सिंह के मामले (1976 पुन एलजे 489) (सुप्रा) में एकल पीठ के फैसले के संदर्भ से पता चलेगा कि उसमें प्राथमिक प्रश्न खंड के तहत आबादी देह के भीतर स्थित भूमि को पंचायत में निहित करने के संबंध में था (क) 1961 अधिनियम की धारा 4(1) का। यह उसके खंड (बी) के तहत किसी गैर-मालिक के घर के अधीन भूमि के निहित होने का मामला नहीं था। इसलिए बाद वाला प्रावधान निर्माण के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। हालाँकि, रिपोर्ट के पैराग्राफ-5 में एक संक्षिप्त टिप्पणी यह दी गई थी कि आबादी देह भूमि न तो पंचायत में निहित है और न ही गैर-मालिकों में। जहां तक गैर-मालिक के घर के नीचे की भूमि का संबंध है, यह अवलोकन एक ओबिटर तानाशाही की प्रकृति में था। लेकिन अगर इसे इस प्रस्ताव के वारंट के रूप में पढ़ा जाए कि धारा 4(1) का खंड (बी) आबादी देह के भीतर की भूमि पर बिल्कुल भी लागू

नहीं है, तो दर्ज किए गए कारणों के लिए यह अच्छा कानून नहीं है। पहले और इसके द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है।

16. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अपीलकर्ता की ओर से दृढ़ निर्भरता मुख्य रूप से रघबीर सिंह के मामले (1965 क्यूआर एलजे 154) (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों पर थी। इसमें दी गई टिप्पणियाँ निस्संदेह अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए रुख का समर्थन करती हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि मामले को पीठ के समक्ष पर्याप्त रूप से नहीं रखा गया था। प्रावधान के विधायी इतिहास और इसके लिए आवश्यक प्रासंगिक निर्माण के बारे में दूर-दूर तक विज्ञापित नहीं किया गया था। 1954 में शामिलात कानून के प्रारंभ होने की कट-ऑफ तिथि के तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही उन जमीनों पर गैर-मालिकों के लंबे समय से चले आ रहे सहमतिपूर्ण कब्जे की मान्यता के औचित्य पर ध्यान दिया गया, जिस पर उन्होंने अपने घर बनाए थे, वास्तव में, विधायिका का इरादा वैधानिक सुरक्षा प्रदान करना था। अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ, मेरा विचार है कि रघबीर सिंह के मामले (सुप्रा) में इस संदर्भ में की गई टिप्पणियाँ कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करती हैं और मैं इसे खारिज करता हूं।

17. अंत में निष्कर्ष निकालने के लिए प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया गया है। यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 4(1)(ए) के प्रावधान आबादी देह के भीतर स्थित भूमि पर लागू होते हैं (इस तथ्य के बावजूद कि वे उक्त धारा 2(जी) के तहत शामिलात देह की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं) अधिनियम या नहीं), जो शामिलात कानून के प्रारंभ होने पर या उससे पहले एक गैर-मालिक के स्वामित्व वाले घर के अधीन है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (एच) में परिभाषित किया गया है।

18. अब, एक बार जब इसे उपरोक्त मान लिया जाता है, तो अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह स्वीकार करने में स्वयं बहुत निष्पक्ष थे कि मामला उसके खिलाफ समाप्त हो जाएगा और निर्धारण के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं बचा है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है और निचली अदालतों के निर्णयों की पुष्टि की जाती है। इसमें शामिल मुद्दे की जटिलता को देखते हुए, हम पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ते हैं।

प्रेमचंद जैन, जे.

19. मैं सहमत हूं.

एससी मितल, जे.

20. मैं सहमत हूं.

21. अपील खारिज.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा